दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

सितंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **5**

- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 5
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 5
- सागर ज़िले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभयारण्य 6
- शक्ति पटेल को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 6
- मध्य प्रदेश विधानसभा में दो नई समितियाँ गठित 6
- 'इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस' 7
- प्रदेश की पहली यात्री 'पिंक बस' 7
- माइक्रोसॉफ्ट और राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच एम.ओ.यू. 8
- मध्य प्रदेश पॉवर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना 8
- ओरछा का ग्राम लाडपुराखास यूएन डब्ल्यूटीओ अवॉर्ड में नामांकित 9

नोट :

- अखिल भारतीय बाघ आकलन 10
- रातापानी अभयारण्य 10
- सागौन उत्पाद प्रोत्साहन 10
- मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक 11
- राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर 11
- राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग 12
- न्यायाधीश रवि मलिमथ 12
- पुराने बांधों की सफाई 13
- एलोपैथी की तर्ज़ पर होम्योपैथी में भी सुपर स्पेशियलिटी उपचार 13
- इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण से लाल मक्के के डीएनए में परिवर्तन 13
- राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 14
- 'नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा' 14
- उच्च न्यायालय ने नवीन पोर्टल लॉन्च किये 15
- 'माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल-2021' 15

नोट :

- आईएनवीसी इंटरनेशनल अवॉर्ड्स, 2020 16
- मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन 16
- 9वीं राज्यस्तरीय ड्रेगन बोट रेस 16
- 'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0-आत्मनिर्भर लाडली' 17
- मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना 17
- मुस्कान किरार: वर्ल्ड सीनियर आर्चरी 18
- कोई न छूटे टीकाकरण महाभियान-4 18
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 19
- भोपाल के सरकारी कॉलेज का नाम परिवर्तन 19
- चिन्नौर चावल को जीआई टैग 20

नोट :

मध्य प्रदेश

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश में 'नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' संचालित करने की मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिये 31 जुलाई, 2021 तक 'पढ़ना-लिखना अभियान' चलाया गया एवं तत्पश्चात् मार्च 2026 तक 'नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' संचालित किये जाएंगे।
- ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिये संचालित किये जा रहे हैं।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कराना है।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित होगी। प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम राज्य, ज़िला एवं विकासखंड में समग्र शिक्षा अभियान/शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाएगा। साथ ही, निरक्षरों को साक्षर करने में जिन संस्थाओं/व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा, उनको 'अक्षर साथी' कहा जाएगा।
- अक्षर साथियों द्वारा स्वयं की इच्छा से साक्षरता कक्षाएँ संचालित की जाएंगी। इसमें निरक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करवाई जाएगी। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। साक्षरता कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- यह परियोजना राज्य एवं केंद्र के मिश्रित अनुदान से संचालित होगी। इसमें केंद्र एवं राज्य में लागत राशि का अनुपात 60:40 का रहेगा। साक्षरता कार्यक्रम में पाँच वर्षों के लिये 32 लाख 60 हज़ार निरक्षरों को नवसाक्षर करने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये पाँच वर्षों में लगभग 110 करोड़ 84 लाख रुपए का व्यय करने का वित्तीय लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को मध्य प्रदेश की मंत्रि-परिषद ने 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' का संचालन करने के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 117 नए ग्रामों का चयन किया गया है। योजना में चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सीधे लाभान्वित करवाया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में निरंतर जारी रखने का अनुमोदन किया है।
- उल्लेखनीय है कि 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' में भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है, जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है।

नोट :

- ग्राम विकास योजना में अधोसंरचना के कार्यों के अंतरपाटन के लिये भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है। अन्य विकास कार्य अभिसरण के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा ग्राम का समग्र विकास कर आदर्श ग्राम घोषित किये जाने का प्रावधान है।

सागर ज़िले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड (State Wildlife Board) की बैठक में सागर ज़िले में नए वन्य जीव अभयारण्य के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभयारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्त्वपूर्ण पहल की है।
- वन विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25 हज़ार 864 हेक्टेयर (25,864 वर्ग किमी.) क्षेत्र अभयारण्य के लिये चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम 'डॉ. भीमराव अंबेडकर' अभयारण्य उत्तर सागर होगा।
- प्रस्तावित अभयारण्य के 5 किमी. की परिधि में 88 ग्राम हैं, जिनकी निस्तार व्यवस्था वनों पर आश्रित है। अभयारण्य क्षेत्र में 98.202 घन मीटर इमारती एवं 236 घनमीटर जलाऊ काष्ठ की अनुमानित राशि वार्षिक क्रमश: 42 लाख एवं 4.96 लाख रुपए प्रभावित होना आँकी गई है।

शक्ति पटेल को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर मंडला ज़िले के शिक्षक शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वर्चुअल कार्यक्रम में देश के 44 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किये गए।
- ज्ञातव्य है कि 32 वर्षीय शक्ति पटेल मंडला ज़िले के ग्राम मांद के शासकीय हाई स्कूल में हिंदी विषय के माध्यमिक शिक्षक हैं।
- इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया तथा क्यूआर कोड द्वारा नि:शुल्क नोट्स बच्चों को वितरित किये। इनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मनोरंजक शिक्षण सामग्री से देश के हज़ारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही इन्होंने हिंदी विषय के पाठों की घटनाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़कर पढ़ाने पर महत्त्व दिया।
- उल्लेखनीय है कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में काम कर रहे प्रतिभाशाली शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिये वर्ष 1958 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी।
- 5 सितंबर, 1962 को भारत में पहली बार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया था।
- इसी तरह 5 सितंबर, 2021 को ही मध्य प्रदेश में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 2021 के ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के 27 शिक्षकों को शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश विधानसभा में दो नई समितियाँ गठित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा की नियम समिति ने सदन को दो नई समितियाँ बनाने की सिफारिश की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सभापतित्व वाली नियम समिति ने विधानसभा में कार्य की अधिकता व अनुभव के आधार पर बेहतर कार्य के लिये इन समितियों के गठन हेतु सिफारिश की है।
- पहली समिति का नाम 'शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति' तथा दूसरी समिति का नाम 'पिछड़े वर्ग हेतु कल्याण समिति' रखा गया है।
- नियम समिति के अनुसार विधायकों के साथ शासकीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार संबंधी विषयों की निगरानी के लिये 'शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति' बनाई जाने की सिफारिश की गई है।
- विधायक द्वारा स्पीकर को की गई असम्मानजनक व्यवहार की शिकायत को परीक्षण के उपरांत स्पीकर जाँच हेतु शिष्टाचार समिति को सौंपेंगे। गंभीर शिकायत होने पर स्पीकर इसे विशेषाधिकार समिति को भी सौंप सकेंगे।
- उपरोक्त नई समिति संबंधित मामलों की जाँच के लिये पहले से विद्यमान सदस्य सुविधा समिति के अतिरिक्त होंगी।
- पिछड़े वर्ग के मामलों की देखरेख के लिये गठित पिछड़े वर्ग की कल्याण समिति को पहले से विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी कल्याण समिति को तोड़कर बनाया जाएगा।

'इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस'

चर्चा में क्यों ?

- 7 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को 'नील गगन के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' (International Day of Clean Air for Blue Skies) पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर विपरीत प्रभावों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को संकल्प पारित कर 7 सितंबर को 'इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस्' आयोजित करने का निश्चय किया गया था।
- पहली बार 7 सितंबर, 2020 को आयोजित पहले कार्यक्रम की थीम 'क्लीन एयर फॉर ऑल' थी, इस बार का विषय, 'हेल्दी एयर, फॉर हेल्दी प्लैनेट' है।
- अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय अधिकारियों को शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारणों से आम जनता को जागरूक करने हेतु अधिकतम लोगों की सहभागिता के साथ वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए।
- साथ ही उन्होंने परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से 'नॉन अटेनमेंट सिटी' के लिये बनाए गए एक्शन प्लान के क्रियान्वयन से लोगों को परिचित कराने के निर्देश दिये।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' चलाया जा रहा है। इसमें देश के 132 शहरों में से मध्य प्रदेश के 6 शहर- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर एवं देवास शामिल हैं। इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कार्य-योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य भी किया जा रहा है।

प्रदेश की पहली यात्री 'पिंक बस'

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री ऊषा ठाकुर ने नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के साथ इंदौर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) द्वारा संचालित प्रदेश की पहली पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- एआईसीटीएसएल द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है।
- इस बस में दो महिला ड्राइवर 'रितु नरवाले' और 'अर्चना कटारे' तथा महिला परिचालक के रूप में 'लक्ष्मी असवरा' व 'पुष्पा चौहान' कार्यरत् हैं।
- पिंक बस में दोनों महिला ड्राइवर को बस चलाने का एक माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये पिंक बसें सीसीटीवी कैमरे, ऑन बोर्ड यूनिट, सेंसर डोर जैसी नवीन तकनीकों से युक्त हैं। इस बस में प्रतिदिन लगभग दो हज़ार महिलाएँ सफर कर सकेंगी।
- मंत्री ऊषा ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि महिला ड्राइवर द्वारा संचालित प्रदेश की पहली यात्री 'पिंक बस' महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण की पहचान है।
- उन्होंने एआईसीटीएसएल को इस सेवा के लिये शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इंदौर ने इस प्रकार की सेवा प्रारंभ कर अन्य ज़िलों को प्रेरणा दी है और भविष्य में भी इस प्रकार की महिला सशक्तीकरण की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट और राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के शुजालपुर में डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित सहायता देने के लिये राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (State Board of Open School Education) और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के 53 ई.एफ.ए (एजुकेशन फॉर आल) स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक के ज्ञान के साथ भविष्य में वैश्विक स्तर पर आई.टी. रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- इसी सत्र से कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को तथा अगले सत्र से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विषय के रूप में चुनने की सुविधा मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस विषय के लिये ऑनलाइन क्लासेस संचालित करेगी।
- माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर 240 घंटे का वार्षिक पाठ्यक्रम और पुस्तक प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही आगामी वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विषय के अध्यापन के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के 53 ई.एफ.ए. स्कूलों में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने विगत वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहायता की है। इससे लगभग 1500 शिक्षक एवं 40 हज़ार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

मध्य प्रदेश पॉवर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पॉवर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिये बिना इनहाउस साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है।

नोट :

- इस योजना का अनुमोदन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी इंडिया) ने किया है तथा भारत सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया।
- यह पॉवर सेक्टरों में साइबर अटैक को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। यह लोड डिस्पैच सेंटर में स्थापित सभी कंप्यूटर प्रणालियों की साइबर सुरक्षा से संबंधित है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसके लोड डिस्पेच सेंटर को आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिये प्रदाय किया जाता है।
- इस प्रणाली को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी साइबर अटैक से सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
- गौरतलब है कि गत वर्ष मुंबई की बिजली प्रणाली इस साइबर अटैक का शिकार हुई थी, जिसके कारण मुंबई में घंटों विद्युत व्यवधान रहा था। इस घटना के बाद ही समूचे देश के पॉवर सेक्टरों को इस तरह की साइबर सुरक्षा तैयार करने के निर्देश केंद्र शासन द्वारा दिये गए थे।
- यह प्रणाली राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता के.के. प्रभाकर एवं अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के प्रयासों द्वारा तैयार की गई।
- इससे पूर्व मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लोड डिस्पैच सेंटर, जबलपुर को एबीटी मीटरिंग प्रणाली (उपलब्धता आधारित शुल्क प्रणाली) एवं स्काडा सिस्टम लागू करने वाले देश के पहले पॉवर यूटिलिटी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।

ओरछा का ग्राम लाडपुराखास यूएन डब्ल्यूटीओ अवॉर्ड में नामांकित

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा के ग्राम लाडपुराखास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइज़ेशन अवॉर्ड में 'बेस्ट टूरिज्म विलेज'श्रेणी के लिये नामांकित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही दो अन्य ग्राम मेघालय और तेलंगाना से नामांकित किये गए है।
- गौरतलब है कि पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ते हुए ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रदेश में 'ग्रामीण पर्यटन' परियोजना प्रारंभ की गई है।
- अगले पाँच वर्षों में 100 गाँवों को ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इनमें ओरछा, खजुराहो, मांडू, साँची, पचमढ़ी, तामिया, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, पेंच एवं कान्हा नेशनल पार्क, मितावली, पड़ावली आदि क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का चयन कर विकास किया जाएगा।
- ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत 6 मुख्य घटकों- क्षेत्रीय पर्यटन आधारित गतिविधियाँ, पर्यटकों के ठहरने के लिये सुविधाजनक आवास/होम-स्टे, परंपरागत एवं स्थानीय भोजन, सांस्कृतिक अनुभव, कला एवं हस्तकला तथा युवाओं में कौशल उन्नयन पर कार्य किया जा रहा है।
- इससे स्थानीय समुदाय को अपने क्षेत्र में पर्यटन के विकास से सीधा लाभ प्राप्त होगा। टूरिज्म बोर्ड समुदाय की भागीदारी से पर्यटन उत्पादों को विकसित करने का प्रशिक्षण भी दे रहा है।
- 'ग्रामीण पर्यटन'स्थानीय संस्कृति और परंपरा के महत्त्व को बनाए रखते हुए स्थानीय लोगों को पर्यटकों की रुचि और आवश्यकता के बारे में जानने का अवसर उपलब्ध कराता है।
- ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से पर्यटक भी स्थानीय सांस्कृतिक विशिष्टता के आवास विन्यास, स्थानीय भोजन के प्रकार एवं प्रक्रिया, पहनावा, बोली, रीति-रिवाज़, परंपराएँ, आवागमन के स्थानीय साधन, आभूषण, शृंगार गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, चित्रकला, अनाज एवं भोजन के संरक्षण के तरीके, स्थानीय खेलकूद, सामाजिकता और आर्थिक सत्कार के तरीके आदि से परिचित होंगे।

नोट :

अखिल भारतीय बाघ आकलन

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2021 को अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के लिये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व होशंगाबाद के पचमढ़ी में वृत्त स्तरीय नोडल अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है। इस वर्ष यह आकलन अक्तूबर से दिसंबर तक तीन महीने चलेगा।
- बाघ आकलन तीन चरणों में किया जाता है। इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सभी वन बीटों में माँसाहारी एवं शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपस्थिति संबंधी साक्ष्य इकट्ठे किये जाते हैं।
- द्वितीय चरण में जीआईएस मैप का वैज्ञानिक अध्ययन और तृतीय चरण में वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रेप लगाकर वन्य प्राणियों के फोटो लिये जाते हैं।
- इस वर्ष पेपरलेस तरीके से विशेष मोबाईल एप एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल के जरिये बाघों के आँकड़े एकत्रित होंगे।
- इसके साथ ही टाइगर रिज़र्व के अलावा क्षेत्रीय वन मंडल एवं निगम क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से शाकाहारी-माँसाहारी वन्य-प्राणियों की गणना पर जोर दिया जाएगा। इसके लिये मैदानी कर्मचारियों को बाघ गणना के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है।

रातापानी अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

- 10 से 12 सितंबर, 2021 तक चले तितली सर्वेक्षण के दरम्यान मध्य प्रदेश के रातापानी अभयारण्य में 14 राज्य के 88 विशेषज्ञों ने 21 कैंप के 80 ट्रेल्स पर पैदल गश्त कर 103 विभिन्न प्रजाति की तितलियों की खोज की एवं इसे सूचीबद्ध किया।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की पंचमढ़ी बुश ब्राउन, एंगल्ड पायरेट, ब्लैक राजा, नवाब कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई-कलर्ड पाइड प्लेट तितलियाँ मिली हैं।
- इस सर्वेक्षण में वाइल्ड वारियर्स और तिंसा फाउंडेशन की विशेष भागीदारी रही है।
- सर्वेक्षण के अंतिम दिन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के.एम.एन. और संजय शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।

सागौन उत्पाद प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

- 11 सितंबर, 2021 को सागौन उत्पाद प्रोत्साहन के लिये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत सागौन उत्पाद मात्रा का आकलन कर इसमें वृद्धि की संभावनाओं को तलाशते हुए उत्पादों के मूल्य-संवर्धन को सूचीबद्ध कर विपणन की रणनीति तैयार की जाएगी।
- वन विभाग ने 'एक ज़िला-एक उत्पाद' योजना में बैतूल ज़िले के सागौन काष्ठ के प्रारंभिक प्र-संस्करण और सागौन काष्ठ के उत्पाद बढ़ाने वाले शिल्पकारों और संस्थानों की सूची तैयार की है।
- उत्पादों के मूल्य-संवर्धन की संभावनाओं को सूचीबद्ध कर इनके विपणन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिये अखिल भारतीय काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलुरू और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से सहयोग लिया जाएगा।

नोट :

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरीफॉरवर्ड पदों तथा नि:शक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
- एथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी मे किये गए पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की ओर से 7 वर्ष के लिये प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- इकाइयों के लिये भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिये विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय इस आशय का 5 लाख रुपए का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा कि उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशि या 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, देना होगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मानसिक चिकित्सालय, इंदौर का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन किये जाने के लिये नवीन एस.ओ.आर. दरों के अनुसार परियोजना हेतु 33.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति और संस्था में पूर्व से स्वीकृत 25 पदों को समर्पित करते हुए 13 नवीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग और विपणन अधोसंरचना नवीन योजना का अनुमोदन किया गया। योजना के परियोजना अभिलेख (DPR) में प्रमुखत: तीन मदों- ब्रांड प्रमोशन, ई-कॉमर्स प्रचार-प्रसार और विपणन अधोसंरचना विकास में व्यय किया जाएगा।
- यह नवीन योजना सभी ग्रामोद्योगी उत्पाद, मृगनयनी (हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद), कबीरा (खादी उत्पाद), विंध्या वैली (ग्रामोद्योग उत्पाद) और प्राकृत (रेशम उत्पादों) के लिये लागू होगी।

राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि उत्तर भारत के लिये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कीरतपुर (इटारसी) में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस केंद्र का उद्देश्य भारतीय गो-भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, आनुवंशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्मप्लाज्म का प्रदाय और देशी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा देश में दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एनकेबीसी) की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश के कीरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में एनकेबीसी की स्थापना की जा रही है।

नोट :

- प्रथम चरण में गायों की 13 नस्लें- साहीवाल, गिर, कांकरेज, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, मालवी, निमाड़ी, केनकथा, खिलारी, हरियाणवी, गंगातीरी एवं गावलाव और भैंस की चार नस्लें- नीली राबी, जाफराबादी, भदावरी तथा मुर्रा संधारित की जानी हैं।
- वर्तमान में कीरतपुर केंद्र पर गायों की गिर, साहीवाल, थारपरकर, निमाड़ी, मालवी, कांकरेज, रेड सिंधी, राठी एवं खिलारी नस्ल की 195 और भैंस की मुर्रा, नीली राबी, भदावरी और जाफराबादी नस्ल की 107 सहित हरियाणा, राठी, कांकरेज, निमाड़ी, मालवी, केनकथा और जाफराबादी नस्लों के 9 सांड उपलब्ध हैं।
- राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक एच.बी.एस. भदौरिया ने बताया कि ब्रीडिंग सेंटर केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत 25 करोड़ रुपए की सहायता से 270 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

चर्चा में क्यों ?

- 15 सितंबर, 2021 को राज्य शासन द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम परिवर्तित कर 'मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग' कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 28 जनवरी, 2008 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया था।
- नाम परिवर्तन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की उप-सचिव मनीषा सेतिया ने आदेश जारी कर दिये हैं।
- ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की थी।

न्यायाधीश रवि मलिमथ

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ का स्थानांतरण कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज़ियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- इससे पूर्व न्यायमूर्ति रवि मलिमथ 28 जुलाई, 2020 से 6 जनवरी, 2021 तक उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके उपरांत वहाँ के कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे।
- 25 मई, 1962 को जन्में न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने 28 जनवरी, 1987 से अधिवक्ता के रूप में कर्नाटक हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, कंपनी, सेवा मामलों आदि में 20 वर्षों तक प्रैक्टिस की। इन्हें संविधान विशेषज्ञ माना जाता है।
- ये 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे।
- ये 24 मई, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

नोट :

पुराने बांधों की सफाई

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप अमृत महोत्सव के तहत देश में पहली बार बांधों की मशीनों के ज़रिये सफाई की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बांधों की सफाई (डिसिल्टिंग) को लेकर विशेषज्ञों के मध्य इसकी उपयोगिता एवं आर्थिक वहनीयता को लेकर मतभेद हैं, जिससे बड़े-बड़े बांध दशकों पुरानी संरचना मात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसे में बांधों की सफाई का यह निर्णय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- बांधों की सफाई का यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश की बरगी तहसील में बनी रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) से प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्य के लिये हाइड्रोलॉजिकल प्रेशराइज्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बरगी बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इसकी सफाई किये जाने से नर्मदा नदी पर निर्मित अन्य बांधों, जैसे- महेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं सरदार सरोवर बांध को भी फायदा होगा।

एलोपैथी की तर्ज़ पर होम्योपैथी में भी सुपर स्पेशियलिटी उपचार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा होम्योपैथी में फेलोशिप पाठ्यक्रम को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिये देश में पहली बार भोपाल के सरकारी होम्योपैथी कॉलेजों में छह महीने का पेलोशिप कोर्स वर्तमान सत्र से शुरू किया जा रहा है।
- फेलोशिप के लिये 20 विषयों, जैसे- डायबिटीज मैनेजमेंट, अस्पताल प्रबंधन, फॉर्माकोविजिलेंस आदि का चयन किया गया है।
- इस पहल से होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं-
  - होम्योपैथी कॉलेजों में विशेषज्ञ क्लीनिक शुरू हो सकेंगे।
  - इन चिकित्सकों का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी सरकारी योजनाओं में किया जा सकेगा, जिससे चिकित्सकों की उपलब्धता के संबंध में क्षेत्रीय विषमता कम होगी।
  - होम्योपैथी अस्पतालों में खास तरह की बीमारियों जैसे- ओबेसिटी, जेरियाट्रिक बीमारियाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आदि के इलाज के लिये अलग से इकाई बनाई जा सकेगी। परिणामस्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुँच हो सकेगी।

इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण से लाल मक्के के डीएनए में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में इंदौर के कस्तूरबा ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण की सहायता से लाल मक्के के बीज के डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर द्वारा राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के सहयोग से किया गया है।
- गौरतलब है कि लाल मक्के में कैंसररोधी गुण के साथ-साथ प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है अत: इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये यह प्रयोग किया गया है।

नोट :

- इस आनुवंशिक परिवर्तन से न केवल लाल मक्के की ऊँचाई कम होगी, बल्कि इसके भुट्टे की लंबाई में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, जैसे- कैंसर उपचार, पर्यावरणीय प्रदूषकों, जैसे- VOCs (Volatile organic compounds) के उपचार, खाद्य परिरक्षण आदि।

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिये गठित चयन समिति की बैठक में तीन वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई और पुरस्कार के लिये श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एन.एस.एस. पुरस्कारों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, सीनियर सेकेंडरी (+2) परिषदों, एन.एस.एस. इकाईयों/कार्यक्रम अधिकारियों और एन.एस.एस. स्वयंसेवकों द्वारा स्वयंसेवी सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिये गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना एवं पुरस्कृत करना है, ताकि एन.एस.एस. को आगे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके।
- बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से राज्यस्तरीय पुरस्कारों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 20 किया जाएगा। स्वयं-सेवक स्तर पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली 11 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 21 हज़ार रुपए करने की अनुशंसा की गई।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के तहत विश्वविद्यालयस्तरीय कार्यक्रम समन्वयक के लिये प्रतिवर्ष एक, ज़िला संगठक स्तर पर दो तथा संख्या स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को 12 प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- इसके अतिरिक्त स्वयं-सेवक स्तर पर 18 पुरस्कार प्रदाय किये जाते हैं। इनमें महाविद्यालय स्तर के 13 स्वयं-सेवक, जिनमें 3 छात्राओं का होना आवश्यक है तथा 5 स्वयं-सेवक विद्यालय स्तर के होंगे, जिनमें एक छात्रा अनिवार्य होगी। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर कुल 12 पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उदेश्य सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये अवसर प्रदान करना है।
- गौरतलब है कि 24 सितंबर, 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में NSS कार्यक्रम शुरू किया था। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय है- 'मैं ही नहीं आप भी'।

'नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा'

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की संस्थापक भारती ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पुस्तक 'नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा' भेंट की।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में नर्मदा परिक्रमा करते हुए दृष्टिगत होने वाली प्रकृति, उसके भिन्न-भिन्न शोभायमान रूप, जनजातीय बंधुओं से मिला सहयोग और बाँध के कारण विस्थापितों की जिज्ञासा से संबंधित अनुभवों को बटोरा गया है।
- भारती ठाकुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर वर्ष 2010 में निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह संस्था गरीब बच्चों के लिये बालबाड़ी से लेकर हाईस्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है।
- इस संस्था द्वारा निमाड़ अंचल के छात्रों को वेल्डिंग, फर्नीचर बनाने, प्लंबिंग, जुड़ाई कार्य, फूड टेक्नोलॉजी, जैविक कृषि तथा गो-विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वनवासी छात्रों की आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है।

नोट :

उच्च न्यायालय ने नवीन पोर्टल लॉन्च किये

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने डैशबोर्ड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, लोक सेवा केंद्र (LSK) के साथ ई-कोर्ट सेवा, ज़िला न्यायालय रिपोर्टिंग सिस्टम, उच्च न्यायालय के मोबाइल ऐप संस्करण 2.0 की लॉन्चिग और हिन्दी में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने कहा कि कार्य-प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिये 'डैशबोर्ड' और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम लॉन्च किये गए हैं। इन विभिन्न ऑनलाइन सिस्टम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का इस्तेमाल कार्यों को गति प्रदान करेगा। उच्च न्यायालय को वादियों और अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट सेवाओं में सुधार के लिये बेहतर आउटपुट एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
- इसी तरह लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-कोर्ट सेवा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों के लिये ई-कोर्ट सेवाओं का एकीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के आईटी विभाग और उच्च न्यायालय की आईटी टीम द्वारा 'लोक सेवा केंद्र' के साथ इसका संचालन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ज़िला न्यायालय रिपोर्टिंग प्रणाली संचालित होगी। इसमें राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय स्तर पर उपयोग के लिये विभिन्न रिपोर्टों की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
- इसके साथ ही, इसमें लंबित प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरणों से संबंधित सारी रिपोर्ट, लंबित प्रकरणों की माहवार और श्रेणीवार जानकारियाँ, पॉक्सो और शीलभंग संबंधी रिपोर्टें, केस क्लियरेंस रिपोर्ट, डिस्ट्रिकवाइस पेंडेंसी रिपोर्ट, इत्यादि सभी जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान सॉफ्टवेयर में किये गए हैं।
- मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 में ज़िला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों की केस संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसकी मदद से उपयोगकर्त्ता/हितधारक उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालयों के ऑनलाइन न्यायालय शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च, 2021 के पहले सप्ताह के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा हितधारकों के लिये मोबाइल ऐप संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया था।
- हिन्दी भाषी राज्यों के ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिये 'हिन्दी' भाषा में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्त्ता मैनुअल जारी किया गया है। इससे केस प्रबंधन को समझने में आसानी होगी। साथ ही सॉफ्टवेयर का संचालन भी आसान होगा।

'माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल-2021'

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव ने 'माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल-2021' का खिताब जीत लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में 17 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2021 तक हुआ था।
- यह पेजेंट माइलस्टोन पेजेंट की ओर से आयोजित 12वाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट था।
- इस प्रतियोगिता में 40 से अधिक देशों की महिलाओं को चुना गया था।
- इस प्रतियोगिता में निष्ठा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा उन्हें इंस्प्रेशन 2021 एवं मिस टैलेंटेड 2021 का खिताब भी मिला।
- निष्ठा ने 'वोकल फॉर लोकल' कॉन्सेप्ट की तर्ज़ पर अपने फाइनल गाउन का डिज़ाइन भोपाल की डिज़ाइनर से करवाया था।

नोट :

आईएनवीसी इंटरनेशनल अवॉर्ड्स, 2020

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2021 को ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में देश की चार नामचीन हस्तियों को INVC इंटरनेशनल अवॉर्ड, 2020 से सम्मानित किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश में पदस्थ भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पवन जैन भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में आईपीएस पवन जैन को जन सेवा के क्षेत्र में किये गए सराहनीय कार्यों तथा खेल विकास एवं हिन्दी कविता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और पुलिस एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किये गए अतिविशिष्ट योगदान के लिये यह अवॉर्ड दिया गया है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में अमेरिका, यूरोप एवं एशियाई देशों से अनेकों हस्तियों ने ऑनलाइन शिरकत की।
- पवन जैन को समाज सेवा के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय कार्य के लिये 1997 में टी.पी. झुनझुनवाला समाजसेवा पुरस्कार, वर्ष 2003 में सराहनीय सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पदक तथा वर्ष 2013 में विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
- भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 1987 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन कुमार जैन सिविल सेवा 1986 में भौतिकशास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान विषय को हिन्दी माध्यम में लिखकर चयनित होने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पहले अधिकारी हैं।
- 6 सितंबर, 2021 को पवन कुमार जैन ने मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन का पदभार ग्रहण किया।

मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्य उत्सव 2021 में मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्ज़िंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव में एम.पी. ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश में निर्यात से संबंधित नए अवसरों को तलाशने के लिये यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का संयुक्त आयोजन था।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न 'डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब' को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक ज़िले में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।
- इसी प्रकार मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों के लिये निर्यात से जुड़ी तकनीकों को समझाने और निर्यातकों को विश्व के प्रमुख आयातकों से जोड़ने में सेतु का कार्य करेगा। एक्सपोर्ट हेल्पलाइन के माध्यम से निर्यातकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भी निर्यात की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। निर्यात की संभावनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वे और वहाँ की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान और उत्कर्ष वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक ज़िले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किये जाने का प्रयास है।

9वीं राज्यस्तरीय ड्रेगन बोट रेस

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भोपाल के छोटे तालाब पर आयोजित 9वीं राज्यस्तरीय ड्रेगन बोट रेस जूनियर बालक/बालिकाओं एवं सीनियर महिला/पुरुष चैंपियनशिप में भोपाल क्लब चैंपियन बना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस रेस चैंपियनशिप को मध्य प्रदेश कायाकिंग एवं केनोइंग संघ द्वारा आयोजित किया गया था।
- इस रेस में 500 मीटर 10+2 मिक्स इवेंट में भोपाल क्लब प्रथम, मध्य प्रदेश अकादमी द्वितीय और एडवेंचर क्लब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- 500 मीटर 10+2 पुरुष इवेंट में भोपाल क्लब ने प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश अकादमी ने द्वितीय एवं भिंड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- 200 मीटर 10+2 पुरुष इवेंट में भोपाल क्लब पहले स्थान पर, भिंड दूसरे स्थान पर तथा एडवेंचर क्लब तीसरे स्थान पर रहा।
- 200 मीटर 10+2 मिक्स इवेंट में मध्य प्रदेश अकादमी प्रथम स्थान पर, भोपाल क्लब द्वितीय स्थान पर तथा एडवेंचर क्लब तृतीय स्थान पर रहा।
- उपर्युक्त प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का चयन 9वीं राष्ट्रीय ड्रेगन वोट रेस सीनियर महिला/पुरुष तथा जूनियर बालक/बालिक प्रतियोगिता 2020-21 के लिये किया जाएगा, जो कि 9 से 12 अक्टूबर, 2021 तक चामरा लेक (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित की जाएगी।

'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0-आत्मनिर्भर लाडली'

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिये लाडली लक्ष्मी योजना को नए स्वरूप 'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0-आत्मनिर्भर लाडली' के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिये वर्ष 2007 में लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना में वर्तमान में 39.81 लाख से अधिक बेटियाँ जुड़ी हुई हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'लाडली लक्ष्मी योजना 2.0-आत्मनिर्भर लाडली' में बालिकाओं के कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में रोज़गार की उपलब्धता, उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया गया है। इससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बेटियों से आग्रह किया है कि वे शाला में प्रवेश से लेकर निरंतर आगे की कक्षाओं में अग्रसर होते हुए लगन, उत्साह और परिश्रम से 12वीं कक्षा तथा उसके बाद भी अपनी रुचि अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हुए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। इससे अन्य बालिकाओं को भी प्रेरणा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना ज़िले के रैगाँव में पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हर वर्ग के गरीब आवासहीनों को रहने के लिये ज़मीन का पट्टा देने हेतु प्रदेश में 'मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना' लागू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के प्रथम चरण में सर्वे करके गरीबों का चिह्नांकन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें उपलब्ध शासकीय ज़मीन में आवासीय प्लॉट दिये जाएंगे। सरकारी ज़मीन उपलब्ध न होने पर निजी भूमि खरीद कर भी गरीबों को दी जाएगी। इस योजना में सतना ज़िले को मॉडल बनाया जाएगा।
- शहरों में जहाँ भूमि उपलब्ध नही होगी, वहाँ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाकर रहने की व्यवस्था की जाएगी।
- जो भूमि, भूमि माफियाओं से मुक्त कराई जाएगी, उसे भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैगाँव में इसी सत्र से कॉलेज खोलने, तहसील भवन के निर्माण के लिये एक करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी। साथ ही 'सीएम राइज स्कूल' खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन एवं ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की।

नोट :

मुस्कान किरार: वर्ल्ड सीनियर आर्चरी

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को यांकटन (अमेरिका) में आयोजित सीनियर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड टीम इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाज़ी अकादमी, जबलपुर की मुस्कान किरार कोलम्बिया के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को रजत पदक दिलाने में कामयाब हुईं।

प्रमुख बिंदु

- कोलम्बिया ने भारत को 229 के मुकाबले 224 अंकों से हराया।
- उल्लेखनीय है कि यांकटन (अमेरिका) में 19 से 26 सितंबर, 2021 तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
- भारत की तरफ से इस टीम इवेंट में मुस्कान किरार (जबलपुर, मध्य प्रदेश), प्रिया गुर्जर (राजस्थान) और ज्योति (आंध्र प्रदेश) शामिल थीं। फाइनल मुकाबले में मुस्कान किरार ने 80 में से 78, प्रिया ने 80 में से 74 और ज्योति ने 80 में से 72 अंक अर्जित किये।
- गौरतलब है कि मुस्कान किरार मूलत: जबलपुर की निवासी हैं। मुस्कान को वर्ष 2018 में राज्य शासन ने एकलव्य पुरस्कार तथा वर्ष 2019 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुस्कान किरार ने एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक अर्जित किया था।
- मुस्कान अब तक 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इन प्रतियोगिताओं में मुस्कान ने एक स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदक सहित भारत को कुल 10 पदक दिलाए हैं।

कोई न छूटे टीकाकरण महाभियान-4

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश में 18 वर्ष आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लिये कोई न छूटे टीकाकरण महाभियान-4 चलाया गया। प्रदेश में 11 हज़ार 472 टीकाकरण केंद्रों पर रात्रि 9.30 बजे तक 12 लाख 3 हज़ार 612 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना से सुरक्षा कवच देने के लिये वैक्सीनेशन महाभियान चलाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। 'कोई न छूटे टीकाकरण महाभियान-4' का आयोजन इस दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है।
- मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में कोई न छूटे टीकाकरण महाभियान-4 में डोर-टू-डोर सर्वे कर वैक्सीन की पहली डोज से वंचित रहे लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई। इसके लिये 57 हज़ार 360 टीकाकर्मियों और 5 हज़ार सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई।
- ऐसे व्यक्ति, जो शारीरिक असमर्थता अथवा अन्य ऐसे ही कारण से टीकाकरण केंद्र नहीं पहुँच पा रहे, उनके लिये 1378 मोबाइल टीम द्वारा टीकाकरण किया गया। टोल-फ्री नंबर 104 और 1075 के माध्यम से लोगों को लगातार सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया।
- कोरोना संक्रमण से प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये ज़िला, ब्लॉक एवं ग्राम और वार्डस्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों ने भी महाभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। समिति के सदस्यों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता का काम करते हुए टीकाकरण केंद्रों पर प्रेरक की भूमिका का निर्वहन भी किया।
- अभी तक प्रदेश की 86% पात्र जनसंख्या को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश पहली डोज लगाने में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 26 सितंबर तक 6 करोड़ 11 लाख 23 हज़ार 864 कोरोना वैक्सीन के टीके लग चुके हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 7 पोषण आहार संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वापस लेकर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंपे जाने के संबंध में निर्णय के साथ ही अन्य निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मार्च 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की आँगनबाड़ियों में गर्भवती/धात्री माताओं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं के लिये टीएचआर प्रदायगी का कार्य स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा किये जाने के लिये 7 टीएचआर संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
- उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देवास, धार, होशंगाबाद, मंडला, सागर, शिवपुरी एवं रीवा में संयंत्र स्थापित किये गए। इन सभी संयंत्रो से (भोपाल संभाग के ज़िले छोड़कर) प्रदेश के अन्य सभी ज़िलों में रेडी टू ईट टेकहोम राशन (टीएचआर) दिया जा रहा है। टीएचआर उत्पादन एवं प्रदायगी कार्य राज्य आजीविका फोरम द्वारा गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंपा गया था।
- मंत्रिपरिषद ने धान के विक्रय के लिये रिज़र्व प्राईज/ऑफसेट मूल्य के निर्धारण, निविदा प्रक्रिया के निर्धारण एवं नीलामी में प्राप्त दरों के अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने, आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिये गठित 'मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग' के गठन के अनुसमर्थन का निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन का अनुमोदन किया। निर्णय अनुसार-
  - बड़े ज़िले (रेत की अधिक मात्रा) में एक-से-अधिक समूह बनाकर निविदा जारी की जाएगी।
  - रुपए 250 एवं निविदाकृत रेत मात्रा का गुणनफल प्रारंभिक आधार मूल्य (ऑफसेट प्राइज) निर्धारित किये जाएंगे।
  - रेत समूह की निविदा का प्रकाशन राज्यस्तर से करने के बाद निविदा (ई-टेंडर) की सभी प्रक्रियाएँ विकेंद्रीकरण कर ज़िले स्तर से करने एवं रेत ठेकेदार से अनुबंध ज़िला स्तर पर किये जाएंगे।
  - रेत समूह के ठेके की अवधि जून 2023 नियत की जाएगी।
- मंत्रिपरिषद ने ग्राम सतगढ़ी, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वसुविधा युक्त 'खेल ग्राम' का जन-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण का निर्णय लिया।

भोपाल के सरकारी कॉलेज का नाम परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को उच्च शिक्षा विभाग ने भोपाल के शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज भेल के नाम को परिवर्तित कर 'बाबूलाल गौड़ शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज' कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- शासकीय पीजी कॉलेज, भेल (भोपाल) को 28 अगस्त, 1984 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था और जनभागीदारी समिति (जेबीएस) एवं नवरत्न कंपनी 'भेल' द्वारा इसे प्रबंधित किया गया था।
- यह कॉलेज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- यह राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा 'बी++' ग्रेड के साथ मान्यताप्राप्त है।

नोट :

- बाबूलाल गौड़ का जन्म 2 जून, 1930 को ग्राम-नौगीर, ज़िला-प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। वे पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधायक चुने गए थे।
- वे 7 मार्च, 1990 से 15 दिसंबर, 1992 तक मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास तथा पुनर्वास एवं 'भोपाल गैस त्रासदी' राहत मंत्री रहे।
- वे 4 सितंबर, 2002 से 7 दिसंबर, 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे।
- बाबूलाल गौड़ 23 अगस्त, 2004 से 29 नवंबर, 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वे प्रदेश के पहले नेता थे, जो 10 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे थे और सरकार में मंत्री भी रहे। 21 अगस्त, 2019 को उनका निधन हो गया था।

चिन्नौर चावल को जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

- 29 सितंबर, 2021 को राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि चिन्नौर चावल के लिये जीआई टैग के मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के दावे में मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई।

प्रमुख बिंदु

- चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यत: बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है, हालाँकि महाराष्ट्र के भंडारा में भी इसका उत्पादन किया जता है, जिसके लिये महाराष्ट्र द्वारा जीआई टैग का दावा किया गया था।
- बालाघाट में पाई जाने वाली चीकायुक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिये बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है।
- भारत में जीआई टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एंव संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत विनियमित किया जाता है।
- भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया।

The Vision

नोट :